

रजिस्ट्र नं० एल०-३३/एम०एम०/१३-१४/९५



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शुक्रवार, २९ सितम्बर, १९९५/७ आश्विन, १९१७

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

के०

विधान सभा मन्चिवालय

अधिसूचना

शिमला-४, २८ सितम्बर, १९९५

संख्या १-४६/९५-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, १९९५ (१९९५

३०३२-राजपत्र/९५-२९-९-९५--१,२२१.

(३९५१)

मूल्य: १ रुपया ।

का विधेयक संख्यांक 12) जो दिनांक 29-9-1995 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

1995 का विधेयक संख्यांक 12.

## हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमिन होः—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1995 है। संक्षिप्त नाम।

1969  
का 7

2. हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ घ) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन।

“(घघ) “विशेषज्ञ समिति” से इस अधिनियम की धारा 12-क के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;”।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात्:— धारा 5 का संशोधन।

“परन्तु संरचनात्मक डिजाईन से सम्बन्धित प्राक्कलन, योजना (प्लान) विनिर्देश, सामग्री की क्वालिटी, सुरक्षा की बातें (फैक्टर), भार की संगणना का ढंग, उनके अनुरूप होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए हैं और सम्यक् रूप से अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर” से ऐसी अर्हताएं और अनुभव, जो विहित की जाएं, रखने वाला स्नातक इंजीनियर अभिप्रेत है।”

4. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के खण्ड (xvi) में, “और न्यूनतम” शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) में,— धारा 10 का संशोधन।

(i) खण्ड (क) में “उसने” के पश्चात् किन्तु शब्द “आकाशी” से पूर्व “और विशेषज्ञ समिति ने भी” शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खण्ड (अ) में “उसके विचार में” शब्दों के पश्चात् किन्तु “आकाशी” शब्द से पूर्व “और विशेषज्ञ समिति के विचार में भी” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

धारा 11 का  
नशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में—

(क) उप-धारा (1) में, शब्द "राज्य सरकार" के पश्चात् और "आकाशी" शब्द के पूर्व "स्वातंत्र्य (मानविक) इंजीनियरों" में से जो अधिष्ठाता अधियन्ता की पक्ति से नीचे के न हो" शब्द अन्तर्भावित किए जाएंगे; और

(ब) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं (2) और (3) रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) निरीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन उपबन्धित किए जाएं। ऐसे निरीक्षक का समय-समय पर ऐसे रज्जुमार्गों का निरीक्षण करना और यह अवधारित करना भी कर्तव्य होगा कि नया ब्रे ठीक स्थिति में निर्मित किए गए हैं और रखे गए हैं तथा उनको, प्रयोग करने वाले व्यक्तियों और सर्वसाधारण को पूरी सुरक्षा और सुविधा के अनुसार सही तौर पर इस अधिनियम के उपबन्धों में संगत रूप में चलाया जा रहा है :

परन्तु निरीक्षक रज्जुमार्ग और इसके अनुलग्नकों का—

- (i) जहां मनुष्यों को कम से कम तीन मास में एक बार ले जाया जाता है; और
- (ii) जहां पशुओं और मान को कम से कम छः मास में एक बार ले जाया जाता है, निरीक्षण करेगा।

(3) राज्य सरकार अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और सेवकों को भी ऐसे पदनामों से नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य समन्वित कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।"

धारा 12-क  
का अन्तः-  
स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 12-क जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"12-क. विशेषज्ञ समिति.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आकाशी रज्जुमार्ग के डिजाइन, स्थापन और परिचालन का ऐसा ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की ऐसी संस्था से गठित और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी बिहित की जाएं, एक या अधिक विशेषज्ञ समितियां गठित कर सकेगी।

(2) विशेषज्ञ समिति का -

(i) अधिनियम के प्रणामन में सम्बन्धित किसी विषय की बाबत और निम्नलिखित की बाबत भी—

(क) किसी आकाशी रज्जुमार्ग के डिजाइन, परिनिर्माण अथवा स्थिति या उससे सम्बद्ध किसी कार्य ;

(ख) किसी रज्जुमार्ग में परिवर्धन अथवा परिवर्धन या बन्द करने ;

(ग) किसी रज्जुमार्ग के स्वरूप या उसके प्रयोग के ढंग के परिवर्धन में, राज्य सरकार और निरीक्षक की सहायता करना और परामर्श देना कर्तव्य होगा ;

(ii) रज्जुमार्ग और अनुलग्नकों के :—

(क) इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन इसके परिचालन के लिए मजूरी देने से पूर्व, आर्थिक स्तर पर ;

(ख) तत्पश्चात् वर्ष में कम से कम एक बार आकाशी रज्जुमार्ग और अनुलग्नकों का ; और

(ग) ऐसे अन्य अवसरों पर जैसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ; यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण का संस्थान करना कि रज्जुमार्ग सांख्यिक यातायात के लिए उपयुक्त है और इसके उपयोग में कोई संकट अन्तर्निहित नहीं है" ।

8. मूल अधिनियम की धारा 13 में—

धारा 13 का  
संशोधन ।

(i) शीर्षक में शब्द "निरीक्षकों" के पश्चात् और शब्द "को" से पूर्व "और विशेषज्ञ समिति" शब्द जोड़े जाएंगे ; और

(ii) शब्द "निरीक्षक" से पूर्व "यथास्थिति," और "निरीक्षक" शब्द के पश्चात्, "या विशेषज्ञ समिति के सदस्यों" शब्द जोड़े जाएंगे ।

9. मूल अधिनियम की धारा 18 में, "और न्यूनतम" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 18 का  
संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 20 का  
प्रतिस्थापन ।

"जब आकाशी रज्जुमार्ग के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई दुर्घटना हो जाए तो, संप्रवर्तक अनावश्यक विलम्ब के बिना दुर्घटना की सूचना राज्य सरकार और निरीक्षक को भेजेगा ; और संप्रवर्तक का आकाशी रज्जुमार्ग के उस स्टेशन का भार-माध्यक सेवक जो उस स्थान के निकट हो जहाँ दुर्घटना हुई है, या जहाँ कोई स्टेशन नहीं है वहाँ आकाशी रज्जुमार्ग के उस खण्ड के संप्रवर्तक का भार-माध्यक सेवक जिसमें दुर्घटना हुई है ; यथामुम्भव न्यूनतम विलम्ब के, उस जिला के मजिस्ट्रेट को जिसमें दुर्घटना हुई है और उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर यह हुई है या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को जिसे सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, दुर्घटना की सूचना देगा और यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई हो या किसी मानव को गम्भीर शारीरिक क्षति पहुँची हो, तो उसकी सूचना निकटतम शोधप्रालय को भी भेजेगा ।"

धारा 20-क

का अर्थः— जोड़ी जायगी, अर्थात्—  
स्थापित ।

11. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 20-क  
"20-क. बचाव कार्यः—यदि किसी बचाव कार्य के दौरान राज्य सरकार कोई  
व्यय व्ययन करती है तो, संभवतः, राज्य सरकार द्वारा व्ययन व्यय व्ययन करने  
के लिए जारी होगा और यदि संभवतः सम्पूर्ण या इसके भाग को व्ययन करने  
में असफल रहता है तो वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वर्गीकृत होगा" ।

धारा 27 का  
संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) में खण्ड (ड) को  
पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (डड) जोड़ा जायगा, अर्थात्—

"(डड) रजिस्ट्रारी के चलाने और अनुसंधान के लिए नियमित कर्मचारियों की  
अर्हताएं विनियमित करना;" ।

धारा 32 का  
संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में, ==

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (क), (कक) और (ककक)  
रखे जायेंगे, अर्थात्—

"(क) धारा 5 के अधीन संरचनात्मक इंजीनियर की अर्हताएं और अनुभव

(कक) धारा 11 के अधीन नियुक्त निरीक्षक की कृतियां, कृषि और कर्मचारी ;

(ककक) धारा 12-क के अधीन विशेषज्ञ सभित का गठन और इसके सदस्यों  
की नियुक्ति के निवृत्ति और नए, अर्हताएं और अनुभव ;"; और

(ii) खण्ड (घ) में, "और न्यूनतम" शब्दों को जोड़ दिया जायगा ।

धारा 33 का  
संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 33 में, "200" अंक के स्थान पर "पांच हजार"  
शब्द और "50" अंक के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जायेंगे ।

धारा 36 का  
संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 36 में, विद्यमान धारा को उप-धारा (1) के  
रूप में पुनःस्थापित किया जायगा और न्यूनतम निम्नलिखित उप-धारा (2)  
जोड़ी जायगी, अर्थात्—

"(2) यदि संभवतः धारा 33 में रजिस्ट्रारी के पदस्थ में उल्लिखित किसी  
बान को, उस आलय से या यह जानने हुए कि ऐसे कार्य या जोय से  
आकाशी रजिस्ट्रारी पर यात्रा कर रहे या उस पर होने वाले किसी व्यक्ति  
की खाने की संभावना है, करेगा या नहीं करेगा तो वह कारखाना से  
निकली अवधि एक मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो  
सकेगी, बशर्तक होगा" ।

उद्देश्यों और कार्यों का कथन

असामास्य और मुर्षेयों की सम्मानना को वांछनीय और राज्य में आकाशी रज्जुवादी का प्रयोग करने वाले मायियों की मुखा मुनिविचन करने के लिए, यह मुनिविचन करना आवश्यक है कि आकाशी रज्जुवादी आर्ह(0)आर्ह(0)पी(0)पहिना की आकाशों के अनुसार ही और प्रयोग की गई सामग्री भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार हो और संरचनात्मक विज्ञान से सम्बन्धित आकाश, योना (प्लान), विनिर्देश रज्जुवादी में प्रयोग की गई सामग्री की क्वालिटी और सुरक्षा की बातें (कंस्ट्रक्शन्) और भार की संतुलन का हिसा, अर्थात् संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया हो, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकृत तरीकों के अनुसार हो। परिचालन से पूर्व और परिचालन के पश्चात् भी अर्थात् इंजीनियरों और विशेषज्ञ मायियों द्वारा कालिक निरीक्षण किया जाना चाहिए। संरचनात्मक द्वारा रज्जुवादी के परिचालन और अप्रचालन के लिए अर्थात् और अनुमती कार्यवाही करना हो नियोजित किया जाने होगा। क्योंकि रज्जुवादी बनाने वाले बहुत खर्चीले हैं और संरचनात्मक अधिक लाभ कमाने हैं, अतः यह उपलब्ध करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा ऐसे बनाने वालों पर उचित करों की प्रविष्टि करने के लिए रज्जुवादी के संरचनात्मक करी है। इसके अतिरिक्त, संरचनात्मक के द्वारा मायियों में सम्बन्धित कुछ उपलब्धियों को और अधिक कठोर बनाने की भी आवश्यकता है। इस कारण से दिमाचल प्रदेश रज्जुवादी अधिनियम, 1995 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

जय बिहारी लाल खासी,  
समसारी मंत्री।

विमिल।

दिनांक 29 मिनस्वर, 1995

### वित्तीय जापन

अधिनियमित होने पर विधेयक के खण्ड 6 का उप-खण्ड (3) और खण्ड 7, राज्य सरकार को, निरीक्षणालय में अधीनस्थ अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने और एक या अधिक विशेषज्ञ समितियाँ गठित करने के लिए सशक्त करेगा। इसमें 0.05 लाख रुपये (अर्थात्) अतिरिक्त खर्च प्रस्तावित होगा जो राजकोष से पूरा किया जाएगा।

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक के खण्ड 13 द्वारा यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 32, राज्य सरकार को धारा 5 के अधीन संरचनात्मक डिजाइनों, सामग्री की क्वालिटी और रज्जुमार्गों की सुरक्षा की बातों (फैक्टर) के प्रमाणीकरण के लिए मान्यता दिए जाने वाले संरचनात्मक इंजीनियरों की अहंताएँ और अनुभव, धारा 11 के अधीन नियुक्त किए जाने वाले निरीक्षक की पंक्तियों, कृत्यों और फर्तियों के बारे में और विधेयक के खण्ड 7 के अधीन गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें, अहंताएँ और अनुभव विहित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करेगी। इस प्रकार बनाए गए नियम राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे। प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य प्रकार का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी एण्ड आर०) (बी०) ए० (3) 6-1195]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुनः स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।



*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

Bill No. 12 of 1995.

**THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS  
(AMENDMENT) BILL, 1995**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

**BILL**

*to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 1995. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter called the principal Act), after clause (d), the following clause (dd) shall be added, namely:— Amendment of section 2.

“(dd) “Expert Committee” means a Committee constituted under section 12-A of this Act;”.

3. In section 5 of the principal Act, the following proviso and Explanation shall be added, namely:— Amendment of section 5.

“Provided that the estimates, plans, specifications relating to the structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses shall be in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards and shall be duly certified by a qualified structural Engineer.

*Explanation.*—For the purposes of this section a “qualified structural Engineer” means a graduate Engineer having such qualifications and experience as may be prescribed.”

4. In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (xvi), the words “and minimum” shall be omitted. Amendment of section 6.

5. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1),— Amendment of section 10.

- (i) in clause (a), for the words “that he has made a careful inspection”, the words “that he as well as the Expert Committee has made careful inspections” shall be substituted; and
- (ii) in clause (e), after the words “that in his opinion”, the words “as well as in the opinion of Expert Committee” shall be inserted.

6. In section 11 of the principal Act.— Amendment of section 11.

- (a) in sub-section (1), after the words “Inspectors of aerial ropeways”, the words “out of Graduate (Mechanical) Engineers,

not below the rank of an Executive Engineer" shall be inserted; and

- (b) for sub-section (2), the following sub-sections (2) and (3) shall be substituted, namely:—

"(2) The Inspector shall exercise such powers and perform such functions and duties as may be provided by or under the provisions of this Act. It shall also be the duty of such Inspector, from time to time, to inspect such ropeways and to determine whether they are constructed and maintained in a fit condition and working properly to the entire convenience and safety of the persons using them and of the general public and consistent with the provision of this Act:

Provided that the Inspector shall inspect the ropeway and its appurtenances—

- (i) where human beings are carried atleast once in a three months; and
- (ii) where animals and goods are carried at least once in a six months.

(3) The State Government may also appoint other subordinate officers and servants with such designations and assign to them such powers, duties and functions as may be necessary for carrying out the purposes of this Act".

Insertion of  
section 12-A.

7. After section 12 of the principal Act, the following section 12-A shall be added, namely:—

"12-A. Expert Committee.—(1) The State Government may, by notification in the official gazette, constitute one or more Expert Committees consisting of such number of persons, having such knowledge and experience in design, setting up and operating aerial ropeways, and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) It shall be the duty of the Expert Committee, —

- (i) to aid and advise the State Government and the Inspector in regard to any matter connected with the administration of the Act; and also in regard to—
  - (a) design, erection or position of any aerial ropeway or of any work appurtenant thereto;
  - (b) the addition to, or the alteration or closure of an aerial ropeways;
  - (c) the variation of the character of any ropeway or of the mode of use thereof;
- (ii) to conduct inspection of aerial ropeways and appurtenances—
  - (a) at the initial stage, before the sanction is granted for its operation under sub-section(1) of section 10 of this Act;
  - (b) subsequently at least once in a year; and
  - (c) on such other occasions as may be directed by the State Government;

to ensure that the ropeway is fit for public traffic, and no danger is involved in its use".

8. In section 13 of the principal Act—

Amendment  
of section 13.

- (i) in the heading after the word "Inspectors", the words "and Expert Committee" shall be added; and
- (ii) after the word "Inspector", the words "or as the case may be to the members of the Expert Committee", shall be added.

9. In section 18 of the principal Act, the words "and minimum" shall be omitted.

Amendment  
of section 18.

10. For the existing section 20 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution  
of section 20.

"20. When any accident occurs in the course of working an aerial ropeway, the promoter shall, without unnecessary delay, send notice of the accident to the State Government and to the Inspector; and the promoter's servant-in-charge of the station on the aerial ropeway nearest to the place at which the accident occurred, or where there is no station, the promoter's servant-in-charge of the section of the aerial ropeway on which the accident occurred shall, with the least possible delay, give notice of the accident to the magistrate of the district in which the accident occurred and to the officer-in-charge of the police station within the local limits of which it occurred or to such other magistrate and police officer as the State Government may appoint in this behalf and shall also, if the accident is attended with loss of human life or serious physical injury to any human being, send information to the nearest dispensary".

11. After section 20 of the principal Act, the following section 20-A shall be added, namely:—

Insertion of  
section 20-A.

"20-A. *Rescue operations.*—If the State Government incurs any expenditure during any rescue operation, the promoter shall be liable to pay the expenditure incurred by the State Government and in case the promoter fails to pay the whole or part of it, it shall be recoverable as an arrears of land revenue".

12. In section 27 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (e), the following clause (ee) shall be added, namely:—

Amendment  
of section 27.

"(ee) for regulating the qualifications of the staff employed for running and maintaining the aerial ropeway;"

13. In section 32 of the principal Act, in sub-section (2) —

Amendment  
of section 32.

- (i) for clause (a), the following clauses (a), (aa) and (aaa) shall be substituted, namely:—

"(a) the qualifications and experience of the structural Engineer under section 5 ;

(aa) the powers, functions and duties of an Inspector appointed under section 11;

(aaa) the constitution of the Expert Committee under section 12-A and terms and conditions of the appointment, qualifications and experience of its members;" and

- (ii) in clause (d), the word "and minimum" shall be omitted.

Amendment of section 33. 14. In section 33 of the principal Act, for words "two hundred", the words "five thousand" and for the word "fifty", the words "five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 36. 15. In section 36 of the principal Act, the existing section shall be renumbered as sub-section (1), and thereafter the following sub-section (2) shall be added, namely:—

“(2) If the promoter does anything or omits to do anything, mentioned in section 33, in relation to an aerial ropeway with intent or with knowledge that such act or omission is likely to endanger the safety of any person travelling or being upon the aerial ropeway, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but may extend to five years.”.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To mitigate the chances of mishaps and accidents and also to secure safety of passengers making use of aerial ropeways in the State, there is urgent need to ensure that the aerial ropeways conform to all the requirements of I.R.C. Codes and material used be as per Indian Standards specifications, and the estimates, plans, specifications relating to structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses used in the ropeways are certified by the qualified structural Engineers, to be in conformity with those laid down by the Bureau of Indian Standards. Pre-operational as well as post operational periodical inspection should be conducted by the qualified Engineers and Expert Committees. The promoters must employ qualified and experienced staff for the operation and maintenance of the ropeways. Since aerial rescue operations are very costly and promoters earn heavy profits, it is necessary to provide that the promoters of the ropeways are liable to re-imburse the expenditure to be incurred on such rescue operations by the Government. Apart from this, there is also need to make the penal provisions concerning the lapses on the part of promoters more stringent. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

JAI BEHARI LAL KHACHI,  
*Minister-in-Charge*

SHIMLA :

The 29th September, 1995.

## FINANCIAL MEMORANDUM

Sub-clause (3) of clause 6 and clause 7 of the Bill when enacted will empower the State Government to appoint subordinate officers and servants in the Inspectorate and to appoint one or more Expert Committees. This will involve extra expenditure to the tune of Rs. 0.05 lakhs (recurring) which will be met out of the State Exchequer.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 32 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 as amended by clause 13 of the Bill will empower the State Government to make rules regarding the qualifications and experience of the structural Engineer to be recognised for certification of structural designs, quality of material and factors of safety of ropeways under section 5, the powers, functions and duties of an Inspector to be appointed under section 11 and to prescribe the terms and conditions of appointment, qualifications and experience of the members of the Expert Committee to be constituted under clause 7 of the Bill. The rules so made are to be laid before the State Legislative Assembly. The proposed delegations are essential and normal in character.

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. PWD (B&R)(B)A(3)-6-1/95]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Bill, 1995, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.